



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 1983/चैत्र 3, 1905  
No. 100] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 1983/CHAITRA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य संचालय  
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1983

सां०का०वि० 280 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित  
आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

“सं० आ० 117”

संविधान (राजस्व-वितरण) आदेश, 1983

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्,  
निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् —

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व-वितरण) आदेश,  
1983 है।

2. माध्याह्नक अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस अधिनियम  
के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी  
केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों  
के अनुसार, 1 अप्रैल, 1982 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में,  
निम्नलिखित राज्यों को भारत की संविधान विधि पर भारत किया जाएगा,—

(क) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के  
राजस्व के सहायता-अनुदान के रूप में उक्त सारणी के  
1501 GI/82

स्तम्भ (2) से (6) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियों  
को उन स्तम्भों में उल्लिखित मेकटरी के प्रशासन और सेवाओं  
से संबंधित मानकों के उन्नयन के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व  
और पूंजीगत प्रकृति के व्यय बढ़ें —

सारणी

राज्य	निम्नलिखित से संबंधित मानकों के उन्नयन के लिए				
	न्यायिक प्रशासन	पुलिस प्रशासन	जेल प्रशासन	राजस्व, जिन्ना और जनजाति प्रशासन	स्टाम्प, रजिस्ट्री- करण और खजाना प्रशासन (वास्तव रूप में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंध्र प्रदेश	9.74	303.57	53.20	179.00	—
असम	24.77	154.78	—	219.99	—
बिहार	130.10	300.38	—	896.61	—
हिमाचल प्रदेश	0.93	76.47	—	22.66	5.00
जम्मू-कश्मीर	—	434.02	—	—	—
केरल	—	—	—	6.00	—
मध्य प्रदेश	11.01	199.00	88.51	250.00	5.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मणिपुर	3.48	—	22.17	30.50	—
मेघालय	—	—	—	34.00	—
नागालैण्ड	—	94.65	—	21.80	—
उड़ीसा	—	530.79	91.94	213.63	—
राजस्थान	30.96	—	3.00	154.89	13.12
सिक्किम	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	0.65	227.85	251.72	38.28	—
त्रिपुरा	—	—	—	62.83	—
उत्तर प्रदेश	—	1667.56	317.81	746.25	50.00
पश्चिमी बंगाल	—	115.29	—	—	—

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियाँ, सैक्टरों के प्रशासन और सेवाओं से संबंधित मानकों के उत्पन्न के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर किया गया वास्तविक व्यय, जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं से प्रकट होता है, उस प्रशासन के सामने ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो इस प्रकार अधिक संबन्धित रकम किसी अन्य राशि या राशियों के विरुद्ध, जो उसी प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उस राज्य को सौंपे हो जाएं, समायोजित की जाएगी;

(ख) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियों को, संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1981 और संविधान (राजस्व-वितरण) आदेश, 1982 के अधीन शुद्ध ब्याज के वास्तविक मध्ये संवत्स अनुदान को हिसाब में लेने के पश्चात् इस संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शुद्ध ब्याज के वास्तविक मध्ये, 1 अप्रैल, 1979, 1980, 1981 और 1982 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के नए उधारों और ऋणों मध्ये :

#### सारणी

राज्य	(लाख रुप में)
1	2
हिमाचल प्रदेश	90.00
जम्मू-कश्मीर	3500.00
मणिपुर	400.00
मेघालय	150.00
नागालैण्ड	300.00
उड़ीसा	1200.00
सिक्किम	50.00
त्रिपुरा	400.00

परन्तु यदि वास्तविक उधारों और ऋणों के आंकड़े जैसा कि उन वर्षों के लेखाओं से प्रकट होता है, या उधार पर ब्याज की दरें, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान के अवधारण में हिसाब में लिए गए सुसंगत आंकड़ों से भिन्न हैं तो इस प्रकार संवत्स अनुदान की रकम किसी ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध, जो उसी प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उस राज्य को सौंपे हो जाएं, समायोजित की जाएगी ।

(2) 1 अप्रैल, 1982 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में उप-पैरा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन किसी राज्य को सौंपे कोई राशि या राशियाँ उस राज्य को सौंपे उस राशि या उन राशियों के अतिरिक्त होंगी जो उस वित्तीय वर्ष में संविधान (राजस्व-वितरण) आदेश, 1979 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में उस राज्य को सौंपे हैं ।

जैल सिंह,

राष्ट्रपति

[सं० फा० 19(1)/83-वि० 1]

र० बंकट सूर्य पेरिशाम्नी, सचिव

#### MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1983

G.S.R. 280(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 117”

#### THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1983

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1983.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3(1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1982, as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (6) of the said Table, towards expenditure, of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns :—

TABLE

State	For upgradation of standards relating to				
	Judicial admi- nistra- tion	Police admi- nistra- tion	Jail admi- nistra- tion	Revenue and Tribal admi- nistra- tions	Stamps, Regis- tration and Treasury adminis- trations
(Rs. in lakhs)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Andhra Pradesh	9.74	303.57	53.20	179.00	..
Assam	24.77	154.78	..	219.99	..
Bihar	130.10	300.38	..	896.61	..
Himachal Pradesh	0.93	76.47	..	22.96	5.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jammu & Kashmir	..	434.02	..	..	..
Kerala	..	..	..	6.00	..
Madhya Pradesh	11.01	199.00	88.51	250.00	5.00
Manipur	3.48	..	22.17	30.50	..
Meghalaya	..	..	..	34.00	..
Nagaland	..	94.65	..	21.80	..
Orissa	..	530.79	91.49	213.63	..
Rajasthan	30.96	..	3.00	154.89	13.12
Sikkim	..	..	..	..	..
Tamil Nadu	0.65	227.85	251.72	38.28	..
Tripura	..	..	..	62.83	..
Uttar Pradesh	..	1667.56	317.81	746.25	50.00
West Bengal	..	115.29	..	..	..

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government :

Provided further that if the actual expenditure on such approved programme or programmes relating to any administration, as revealed in the accounts of that year, is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose;

(b) each of the States specified in column (1) of the table below, the sums specified against it in column (2) of the Table towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States, in the financial years commencing on the 1st day of April, 1979, 1980, 1981 and 1982 after taking into account the grants paid towards net interest liability under the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1982

and the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1982 as per the recommendations of the Finance Commission in this regard :—

TABLE	
State	(Rs. in lakhs)
(1)	(2)
Himachal Pradesh	90.00
Jammu & Kashmir	3500.00
Manipur	400.00
Meghalaya	150.00
Nagaland	300.00
Orissa	4200.00
Sikkim	50.00
Tripura	400.00

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the accounts of those years, or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above, the amount of grant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph(1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1982 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1979.

ZAIL SINGH,

President.

[No. F. 19/(1)/83-L.I.]

R.V.S. PERI SASTRI, Secy.

